

अधिसूचनाओं को सदन के पटल पर रखने में हुये  
विलम्ब का कारण

राज्य कर अनुभाग-2 द्वारा निर्गत अधिसूचनाओं को समय से सदन के पटल पर रखे जाने में हुये विलम्ब का कारण "मुद्रित प्रतियाँ राजकीय मुद्रणालय से ससमय प्राप्त न होना एवं विधान मण्डल का द्वितीय सत्र-2020 का अत्यधिक लघु होना है, जो कि प्रक्रियात्मक विलम्ब है।"

योगी आदित्यनाथ  
मुख्यमंत्री



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 30 अप्रैल, 2020

बैशाख 10, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 426/ग्यारह-2-9(47)-17-उ०प्र० अधि०-1-2017-आदेश (104)-2020

लखनऊ, 30 अप्रैल, 2020

अधिसूचना

प०आ०-160

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों (जिन्हें आगे तत्कालीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कहा गया है) को, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (अधिनियम संख्या 31 सन् 2016) के उपबन्धों के अधीन निगमित ऋणी हैं, जो निगमित दिवाला सम्बन्धी समाधान प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और जिनका कार्य प्रबन्ध, अन्तरिम समाधान वृत्तिकों (आईआरपी) या समाधान वृत्तिकों (आरपी) द्वारा किया जा रहा हो, ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती हैं जो आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से निगमित दिवाला सम्बन्धी समाधान प्रक्रिया पूरी होने तक वे नीचे यथाउल्लिखित, अनुवर्ती विशेष प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे।

2-रजिस्ट्रीकरण-ऐसे व्यक्तियों के उक्त वर्ग को, आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से प्रभावी निगमित ऋणी से भिन्न व्यक्ति के रूप में माना जाएगा और प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जहाँ वह निगमित ऋणी रजिस्टर्ड थी, आईआरपी/आरपी की नियुक्ति के तीस दिन के भीतर नया रजिस्ट्रीकरण (जिसे आगे नया रजिस्ट्रीकरण कहा गया है) कराने के लिए उत्तरदायी होगा :

परन्तु ऐसी दशा में, जहाँ आईआरपी/आरपी की इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व नियुक्ति की गई है, वहाँ वह आईआरपी/आरपी, इस अधिसूचना के प्रारम्भ होने से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण कराएगा, जो आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से प्रभावी होगा।

3-विवरणी-ऐसे व्यक्तियों का उक्त वर्ग, रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के पश्चात् उस तारीख से, जिस तारीख को वह रजिस्ट्रीकरण के लिए उत्तरदायी हो गया हो, से उस तारीख, जिस तारीख को रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया हो, तक उक्त अधिनियम की धारा 40क के अधीन पहली विवरणी फाइल करेगा।

4-इनपुट कर प्रत्यय-(1) आईआरपी/आरपी की नियुक्ति से, व्यक्तियों का उक्त वर्ग, उन बीजकों पर जो कि तत्कालीन जीएसटीआईएन पर माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियाँ प्राप्त की हैं, के लिए उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) के उपबन्धों और उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) उक्त अधिनियम के अध्याय 5 की शर्तों और तदधीन बनायी गयी नियमावली के अध्याय 5, के नियम 36 के उपनियम (4) के सिवाय, प्रस्तुत उसकी प्रथम विवरणी में इनपुट कर प्रत्यय उपभोग करने का पात्र होगा।

(2) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिन्होंने, व्यक्तियों के उक्त वर्ग से, आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से उस अवधि के लिए जो इस अधिसूचना में यथापेक्षित रजिस्ट्रीकरण की तारीख तक या इस अधिसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, पूर्व में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के जीएसटीआईएन द्वारा जारी बीजकों पर पूर्तियाँ प्राप्त की हैं, उक्त अधिनियम के अध्याय 5 की शर्तों और तदधीन बनाये गयी नियमावली के उपबन्धों के अधीन, उक्त नियमावली के नियम 36 के उपनियम (4) के उपबन्धों के सिवाय, इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के लिए पात्र होगा।

5-इस अधिसूचना के निबन्धानुसार आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से रजिस्ट्रीकरण की तारीख तक विद्यमान रजिस्ट्रीकरण में, आईआरपी/आरपी द्वारा रोकड़ खाता में निक्षेपित कोई रकम तत्कालीन रजिस्ट्रीकरण में प्रतिदाय के लिए उपलब्ध होगी।

स्पष्टीकरण-इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए "निगमित ऋणी", "निगमित दिवाला समाधान वृत्तिक", "अन्तरिम समाधान वृत्तिक" और "समाधान वृत्तिक" के वही अर्थ होंगे, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (अधिनियम संख्या 31 सन् 2016) में उनके लिये समनुदेशित हैं।

आज्ञा से,  
आलोक सिन्हा,  
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 426/XI-2-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order (104)-2020, dated April 30, 2020:

No. 426/XI-2-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order (104)-2020

*Dated Lucknow, April 30, 2020*

In exercise of the powers conferred by section 148 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby notifies those registered persons (hereinafter referred to as the erstwhile registered person), who are corporate debtors under the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), undergoing the corporate insolvency resolution process and the management of whose affairs are being undertaken by interim resolution professionals (IRP) or resolution professionals (RP), as the class of persons who shall follow the following special procedure, from the date of the appointment of the IRP/RP till the period they undergo the corporate insolvency resolution process, as mentioned below.

2. **Registration** - The said class of persons shall, with effect from the date of appointment of IRP/RP, be treated as a distinct person of the corporate debtor, and shall be liable to take a new registration (hereinafter referred to as the new registration) in each of the States or Union territories where the corporate debtor was registered earlier, with thirty days of the appointment of the IRP/RP :

Provided that in cases where the IRP/RP has been appointed prior to the date of this notification, he shall take registration within thirty days from the commencement of this notification, with effect from date of his appointment as IRP/RP.

3. **Return** –The said class of persons shall, after obtaining registration file the first return under section 40 of the said Act, from the date on which he becomes liable to registration till the date on which registration has been granted.

4. **Input Tax Credit** – (1) The said class of persons shall, in his first return, be eligible to avail input tax credit on invoices covering the supplies of goods or services or both, received since his appointment as IRP/RP but bearing the GSTIN of the erstwhile registered person, subject to the conditions of Chapter V of the said Act and the rules made thereunder, except the provisions of sub-section (4) of section 16 of the said Act and sub-rule (4) of the rule 36 of the Uttar Pradesh goods and Service Tax rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules).

(2) Registered persons who are receiving supplies from the said class of persons shall, for the period from the date of appointment of IRP/RP till the date of registration as required in this notification or thirty days from the date of this notification, whichever is earlier, be eligible to avail input tax credit on invoices issued using the GSTIN of the erstwhile registered person, subject to the conditions of Chapter V of the said Act and the rules made thereunder, except the provisions of sub-rule (4) of rule 36 of the said rules.

5. Any amount deposited in the cash ledger by the IRP/RP, in the existing registration, from the date of appointment of IRP/RP to the date of registration in terms of this notification shall be available for refund to the erstwhile registration.

*Explanation* :- For the purposes of this notification, the terms "corporate debtor", "corporate insolvency resolution professional", "interim resolution professional" and "resolution professional" shall have the same meaning as assigned to them in the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Act no. 31 of 2016).

By order,  
ALOK SINHA,  
*Apar Mukhya Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 128 राजपत्र-2020-(267)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।  
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 30 सा० राज्य कर-2020-(268)-3500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।